

The Hindu-14th July -2024

State may seek relaxation in borrowing limit

THIRUVANANTHAPURAM

Kerala is planning to seek relaxation in its borrowing limit for meeting its financial commitments related to the Centrally assisted Jal Jeevan Mission. » Page 4

JJM expenses: State may seek relaxation in borrowing limit

The Centrally assisted project seeks to provide tap connections to all rural households in the country. It is estimated to cost a little over ₹42,000 cr. in State, shared equally by Centre and State

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

Kerala is planning to seek relaxation in its borrowing limit for meeting its financial commitments related to the implementation of the Centrally assisted Jal Jeevan Mission (JJM) rural household tap connectivity scheme.

Both the Centre and the State have so far spent ₹9,729 crore on the project in the State. The cost of the project is shared equally by the Centre and the State,

with the State releasing a matching share to the Central allocation. The JJM is estimated to cost a little over ₹42,000 crore.

It is understood that Kerala is planning to write to the Centre seeking a relaxation in its borrowing limit equal to the State's share that would be needed to complete the project. Chief Minister Pinarayi Vijayan had indicated the government's plans in this regard while making a statement on timely payment of benefits in the just-concluded session of the

State Assembly. The Chief Minister had pointed out that the government hoped to complete the ongoing JJM works by February 2025.

UDF allegation

Last week, the Opposition United Democratic Front (UDF) had slammed the Water Resources department for lapses in the implementation of the JJM, pointing out that the State had overshot the deadline and would have to shell out close to ₹15,000 crore more to meet its share of

JJM spending. The Opposition had also criticised the government for the poor implementation status of the scheme.

According to data published by the Ministry of Jal Shakti, JJM work in Kerala is yet to touch 55%. Only Rajasthan (51.09%) and West Bengal (50.40%) are below the State on the national-level list.

A national-level project, the Centrally assisted JJM seeks to provide functional household tap connections to all rural households in the country.

Rajasthan Patrika- 14th July -2024

नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में खुलासा, मप से 1.36 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर

जरूरत से ज्यादा खींच रहे पानी, धरती को दे रहे प्लास्टिक कचरा



पत्रिका
हरित
प्रदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश से 1.36 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। यानी इनका जीवन स्तर पहले से सुधरा है। यह बदलाव 2020-21 की तुलना में आया है। हालांकि प्रदेश अभी पर्यावरण, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, न्याय, भूजल दोहन, सस्टेनेबल सिटी की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भूजल दोहन 54.77 से बढ़कर 58.75 प्रतिशत हो गया है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसका उपयोग बढ़ा है। इसका खुलासा नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में हुआ है। कुछ क्षेत्रों में सुधार के चलते राज्य की स्थिति 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर की रही है।

इंडेक्स के अनुसार 97.87% लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज मिल रहा है। कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 98.48 है। 9 से 11 महीने के आयु समूह में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत 93.19 है।



इंडेक्स में यह होता है

एसडीजी इंडिया इंडेक्स सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर रैंकिंग तय करता है। इसमें 16 सतत विकास लक्ष्यों पर अंकों की गणना की जाती है। 65 से 99 अंक प्राप्त करने पर फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

55.57% महिला खाताधारक जनधन योजना में 50 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले

956 है लिंगानुपात जन्म के समय 950 के मुकाबले, वहीं शत प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच गई है

यहां पिछड़ा मध्यप्रदेश

- आत्महत्या दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) 15.10 से बढ़कर 17.90 हो गई।
- सड़क हादसों के कारण मृत्यु दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) 14.35 से बढ़कर 16.20
- सूचीबद्ध कंपनियों में प्रबंधकीय पदों पर महिलाएं (प्रति 1,000) 227 से घटकर 196.61
- कुल रोजगार के प्रतिशत के रूप में विनिर्माण रोजगार 6.84 से घटकर 6.27 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध (प्रति 100,000 अजजा जनसंख्या) 46.70 से बढ़कर 68.20
- एसटी के खिलाफ अपराध (प्रति 100,000 एसटी जनसंख्या) 12.50 से बढ़कर 19.40
- राहरी क्षेत्रों में सड़क हादसों के कारण मौत (प्रति 100,000 जनसंख्या) 17.43 से बढ़कर 20.11
- 100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाले गाई रात प्रतिशत से घटकर 99.95
- प्रति 1,000 जनसंख्या पर उत्पन्न प्लास्टिक कचरा (टन/वर्ष) 0.89 से बढ़कर 1.65
- ट्री कवर (%) 2.71 से घटकर 2.61 प्रतिशत
- मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में वृद्धि (%) 0.86 से बढ़कर 1.46
- संरक्षित क्षेत्र के प्रति एमरक वन्यजीव अपराध के मामले 20.00 से बढ़कर 22.00
- प्रति 100,000 जनसंख्या पर हत्याएं 2.20 से बढ़कर 2.30
- प्रति 100,000 जनसंख्या पर बच्चों के विरुद्ध संश्लेष अपराध 63.30 से बढ़कर 71.00
- प्रति 100,000 बाल जनसंख्या पर लापता बच्चे 36.64 से बढ़कर 39.47
- प्रति 100,000 जनसंख्या पर न्यायालय 2.51 से घटकर 2.39

किस क्षेत्र में कितने अंक मिले

- | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| गरीबी उन्मूलन: 67 | लैंगिक समानता: 48 | अच्छा काम और आर्थिक विकास: 64 | सतत शहरी और सामुदायिक विकास: 86 | भूमि पर जीवन: 90 |
| भुखमरी उन्मूलन: 48 | साफ पानी और स्वच्छता: 87 | उद्योग, नवचार और आधोसंरचना विकास: 39 | जिम्मेवारी के साथ उपभोग और उत्पादन: 92 | शांति और न्याय के लिए संस्थान: 73 |
| अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर: 56 | सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा: 90 | असमानता में कमी: 54 | जलवायु परिवर्तन: 63 | |
| गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: 49 | | | | |

67 कुल अंक